मान्यता दिलाना

28. डॉ० अरूण कुमार--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''कई कॉलेजों के पास नैक की मान्यता नहीं'' के आलोक में क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास (उ०शि०) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों यथा वाणिज्य महाविद्यालय, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, पटना, ट्रेनिंग कॉलेज, पटना कॉलेज, विधि कॉलेज सहित राज्य के कई कॉलेजों के पास नैक (नेशनल असेसमेंट एक्रेडिएशन काउंसिल की मान्यता प्राप्त नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेजों को नैक की मान्यता नहीं रहने से यूजीसी द्वारा विकास मद में फंड नहीं मिल रहा है जिससे कॉलेजों को क्षति हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के उन सभी कॉलेजों को जिसे नैक की मान्यता हासिल नहीं है, उसे मान्यता दिलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

29. श्री रामेश्वर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''मौका मिला तो पहाड़ ही लूट लिया'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत सासाराम प्रखण्ड के धौडाढ़ ग्राम के पास सिंचाई विभाग के अधीन पहाड़ को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पहाड़ माफियाओं के साथ मिलीभगत करके 4 एकड़ पहाड़ की नीलामी कर दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि 4 एकड़ पहाड़ के आड़ में माफियाओं द्वारा पिछले 3 वर्षों से करीब 200 एकड़ पहाड़ का अवैध ढ़ंग से खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रु० की राजस्व की हानि हो रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिंचाई विभाग के उक्त पहाड़ का जो वन क्षेत्र के अधीन आता है उसकी निलामी पर रोक है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध खनन को बन्द कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

क्षति रोकना

30. श्री संजय सिंह टाईगर--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य वृहत खनिज लीज का नवीकरण विगत 16 वर्षों से नहीं होने के कारण राज्य सरकार को प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार वृहत खनिज के लीज का नवीकरण कर राजस्व की हो रही क्षति को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना:
दिनांक 8 मार्च, 2011 (ई०)।

बि०स०मु० (एल०ए०), 131-डी०टी०पी०--450